कानपुर, मंगलवार, 10 मार्च, 2026
वर्षः 03, अंकः 63, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड बिहार में राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को...>Pg12
नगर निगम में महापौर ने खेली फूलों की होली...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

गैस बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव

युद्ध का असर भारत की रसोई तक

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अब एक उपभोक्ता को दो सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अनिवार्य अंतर रखना होगा।

सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण एलपीजी की वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को सीधे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

नई व्यवस्था के तहत 25 दिन से पहले सिलेंडर की दोबारा बुकिंग नहीं की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे गैस की अनावश्यक जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी और वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सकेगी।

इसके साथ ही अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों और आवश्यक सेवाओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। गैर-घरेलू क्षेत्रों में गैस वितरण की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की एक विशेष समिति भी गठित की गई है, जो मांग और आपूर्ति की स्थिति का आकलन करेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत की एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक बाजार में आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए सरकार उत्पादन बढ़ाने और वितरण व्यवस्था को नियंत्रित कर घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।

संभावित असर

- घरेलू गैस और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव
- सरकार को सब्सिडी और आपूर्ति प्रबंधन के कदम बढ़ाने पड़ सकते हैं
- ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक सप्लाई और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत

क्या बदले नियम

- सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर
- जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती
- रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश
- अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को प्राथमिकता आपूर्ति
- गैर-घरेलू उपयोग की समीक्षा के लिए ओएमसी की विशेष समिति

पश्चिम एशिया युद्ध का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर

- भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित दबाव
- भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है।
- इसमें बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आता है, जैसे सऊदी अरब, ईराक, युनाईटेड अरब एमीरेट्स और कतर।
- भारत की एलपीजी खपत का करीब 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है।
- वैश्विक बाजार में तेल-गैस की आपूर्ति बाधित होने पर कीमतों में तेजी और सप्लाई में देरी की आशंका बढ़ जाती है।
- युद्ध लंबा खिंचने पर शिपिंग रूट और बीमा लागत भी महंगी हो सकती है।

गृह मंत्रालय की नई एसओपी लागू, छोटी रकम के मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया से मिलेगी राहत

साइबर ठगी में बड़ी राहतः अब 50 हजार तक की रकम बिना कोर्ट आदेश होगी वापस

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में बढ़ते साइबर अपराध के बीच केंद्र सरकार ने पीड़ितों को राहत देने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। नई व्यवस्था के तहत अब 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी की रकम पीड़ित को बिना अदालत की अनुमति के वापस की जा सकेगी।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर जारी इस नई एसओपी का उद्देश्य साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को जल्द राहत दिलाना है। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के साथ 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी होती है और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसियां बिना न्यायालय की अनुमति के ही रकम रिलीज कर सकेंगी।

अब तक छोटी रकम के मामलों में भी अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य होता था, जिससे पीड़ितों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था से यह प्रक्रिया काफी सरल और तेज हो जाएगी।

दरअसल, साइबर ठगी की शिकायत मिलने पर बैंक संदिग्ध खाते को तुरंत फ्रीज कर देते हैं ताकि रकम आगे ट्रांसफर न हो सके। पहले ऐसे मामलों में खाते को अनफ्रीज करने या रकम जारी करने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी होती थी। नई गाइडलाइन के अनुसार जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों को अधिकतम 90 दिनों के भीतर अनफ्रीज करने का प्रावधान किया गया है।

गोरखपुर जोन के साइबर कमांडो उपेंद्र सिंह के अनुसार नई गाइडलाइन के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे ठगी की छोटी रकम वापस पाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

इसी बीच बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र में साइबर जालसाजों ने बेतौहा गांव के एक व्यक्ति से 2.20 लाख रुपये की ठगी कर ली। जालसाजों ने उसके दोस्त को दुबई में फंसा बताकर पासपोर्ट और वीजा जब्त करने की धमकी दी और क्यूआर कोड भेजकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। गौर थाना प्रभारी अतुल कुमार अंजान ने बताया कि अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या क्यूआर कोड पर भरोसा कर पैसे ट्रांसफर न करें।

नई एसओपी की प्रमुख बातें

- 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी की रकम बिना कोर्ट आदेश वापस
- जांच में शिकायत सही पाए जाने पर एजेंसियां सीधे रकम रिलीज करेंगी
- संदिग्ध खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया जारी रहेगी
- फ्रीज किए गए बैंक खातों को 90 दिनों के भीतर अनफ्रीज करने का प्रावधान
- छोटी रकम के मामलों में पीड़ितों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत

उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एडीजी आलोक सिंह सख्त, दिए कड़े निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोन के सभी जिलों को बताएं कई दिशा निर्देश

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। आगामी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कानपुर जोन में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय बैठक कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में आईजी रेंज झांसी आकाश कुलहरि, डीआईजी रेंज कानपुर हरीश चन्दर सहित जोन के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान तथा पुलिस व प्रशासन के नोडल अधिकारी शामिल हुए।

एडीजी आलोक सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अभ्यर्थियों के प्रवेश और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित रखा जाए तथा नकल या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए।

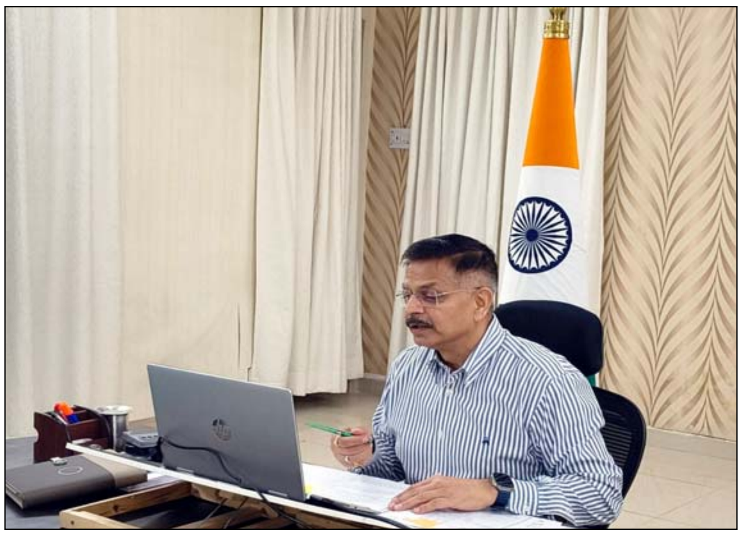

उन्होंने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के भी निर्देश दिए, ताकि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने और आवश्यक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में झांसी के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी व एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला व एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव, कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह व एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय, जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार, कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री व एसपी बिनोद कुमार, फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व एसपी आरती सिंह तथा औरैया के जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी व एएसपी आलोक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एडीजी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा को पूर्ण सुरक्षा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए, जिससे अभ्यर्थियों का विश्वास कायम रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

आईजीआरएस रैंक में दस अंक की लंबी छलांग

75 जिलों में 60वीं रैंक

➪ घाटमपुर तहसील की रैंक काफी लुढ़की

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर. आईजीआरएस रैंकिंग पर सुधार करते हुए दस अंकों की लंबी छलांग मारी है। जिला प्रशासन ने शिकायतों के निस्तारण और निगेटिव फीडबैक पर स्टेप टू स्टेप टाइट मॉनिटरिंग की, जिसका रिजल्ट कुछ हद तक ठीक रहा। 75 जिलों में 87.14 प्रतिशत पाकर 60वीं रैंक और 140 में 122 अंक मिले हैं, पिछले महीने मिली 70वीं रैंक से दस अंक की उछाल है। वहीं पिछली दफा प्रदेश की तहसीलों में परचम लहराने वाली घाटमपुर तहसील की रैंकिंग काफी खराब हुई। जारी रैंक में 139 स्थान मिली, लेकिन अन्य तीन तहसीलों ने रैंक में सुधार किए हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आईजीआरएस रैंक में कुछ सुधार जरूर आई है, अभी और बेहतर की जरूरत है। निगेटिव फीडबैक पर विभागों को लेटर लिखा जाएगा। लापरवाह अफसरों पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश की जारी आईजीआरएस रैंकिंग की लगातार गिरवाट के बाद अब जिले की रैंक में कुछ सुधार हो रहा है। पिछली दफा 70वीं रैंक के बाद अब 60वीं रैंक हासिल की है। अफसरों ने बताया कि निगेटिव फीडबैक वाले विभागों पर कार्रवाई की जा रही है। अफसरों के साथ शिकायतकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। रैंक में और सुधार के लिए अफसरों को लेटर लिखा गया है।

कुछ ढीठ अफसरों से बिगड रहीं रैंक

आईजीआरएस की रैंक को लेकर प्रशासन के आलाधिकारी संबंधित विभागों पर कडा एक्शन नहीं ले रहे जिसके चलते निगेटिव फीडबैक और ऑन टेबल ही शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा। विभागों को नोटिस तो तामिल हो रही, लेकिन कई अफसर इसका जवाब तक नहीं दे रहे। नीचे स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही, यह सब भी केवल खानापूर्ति है।

घाटमपुर तहसील की रैंक सौ जिले के बाहर

पिछले महीने प्रदेश की तहसीलों में शिकायतों के निस्तारण पर प्रथम स्थान रखने वाली घाटमपुर तहसील की रैंक सौ जिले के बाहर हो गई है, लेकिन जिले में वह अव्वल है। घाटमपुर 139 रैंक और 94 प्रतिशत मिले। बिल्हौर 201 रैंक और 89 प्रतिशत मिले। नरवल 85 प्रतिशत और 236 रैंक मिली है। तहसील सदर 86 अंक पाकर 225 रैंक मिली है। घाटमपुर को छोड दें तो तीनों तहसीलों की रैंक में पिछले से काफी सुधार है। वहीं प्रतिशत में भी बढोत्तरी हुई है।

आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई: नगर आयुक्त

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम में जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को नगर निगम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के कड़े निर्देश दिए गए।

बैठक में नगर आयुक्त ने गत माह की प्रगति की तुलना वर्तमान माह के डाटा से करते हुए विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों और संदर्भों की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करें। यदि कोई भी शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में जाती पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मामला शासन को भेजा जाएगा।

नगर आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक निस्तारण के साथ मौके के निरीक्षण के छायाचित्र तथा शिकायतकर्ता से संवाद के प्रमाण आईजीआरएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं, ताकि कार्रवाई की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

समीक्षा के दौरान कुछ मामलों में शिकायतकर्ताओं द्वारा असंतुष्ट फीडबैक दिए जाने पर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भ्रामक या अपूर्ण आख्या लगाना गंभीर लापरवाही है और भविष्य में ऐसी स्थिति मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए, जिससे आम लोगों को समयबद्ध और संतोषजनक समाधान मिल सके।

नगर निगम में महापौर ने खेली फूलों की होली

होली मिलन समारोह में उमड़ा उत्साह

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम मुख्यालय स्थित नगर निगम गेस्ट हाउस में होली मिलन समारोह एवं फूलों की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांडे ने पार्षदों, अधिकारियों और अतिथियों को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं तथा सभी के साथ फूलों की होली खेली। समारोह के दौरान होली गीतों की धुन पर उपस्थित लोग भाव-विभोर नजर आए।

महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि होली रंगों और आपसी भाईचारे का त्योहार है। भारत की संस्कृति इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि यहां सभी पर्व समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देते हैं। होली का पर्व भी लोगों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ जोड़ने का संदेश देता है।

समारोह में महिला मोर्चा की ओर से भी जमकर अबीर-गुलाल उड़ाया गया। इस अवसर पर नगर निगम और जलकल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि, वर्तमान एवं पूर्व पार्षद तथा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा नेता अमित पांडे उर्फ बंटी सहित पार्षद नवीन पंडित नेता सदन, डॉ. अखिलेश वाजपेयी, सौरभ देव, संतोष साहू, विद्या वर्मा, अमित जायसवाल, सुशील अवस्थी, कौशिक वाजपेयी, वंदना शर्मा, पार्षद अर्पित यादव, विजय गौतम, विकास साहू, आकर्ष बाजपेई, नीरज कुरील सहित भाजपा संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अतिथि उपस्थित रहे।

रज्जन-बब्बू पार्क में ऐतिहासिक गंगा मेला का दिखा नजारा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। हटिया स्थित रज्जन-बब्बू पार्क में कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए।

गंगा मेला के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में लोगों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दीं और आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला, जहां उपस्थित लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि गंगा मेला कानपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह पर्व लोगों को आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय नागरिक तथा युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने मिलकर गंगा मेला की परंपरा को आगे बढ़ाने और शहर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प लिया।

रंगों की बारिश के बीच फूटी मटकी

बिरहाना रोड की होली में उमड़ा होरियारों का सैलाब

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। होली के रंग में सराबोर कानपुर शहर में बिरहाना रोड पर आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता ने उत्सव का अद्भुत माहौल बना दिया। होली गंगा मेला पर बिरहाना रोड नवयुवक संघ के तत्वावधान में आयोजित इस पारंपरिक प्रतियोगिता में रंगों की बारिश के बीच युवाओं ने उत्साह और जोश के साथ मटकी फोड़ी। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे होरियारों ने ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया, जिससे पूरा इलाका होली के रंग में रंगा नजर आया।

प्रतियोगिता की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई, जब बिरहाना रोड नवयुवक संघ के पदाधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद अलग-अलग मोहल्लों और युवाओं की टीमों ने मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाकर अपनी ताकत और संतुलन का प्रदर्शन किया। ऊपर ऊंचाई पर बांधी गई मटकी को फोड़ने के लिए प्रतिभागियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

मटकी के आसपास लगातार रंग और गुलाल उड़ाए जा रहे थे, वहीं ऊपर से रंगों और पानी की बौछार भी की जा रही थी, जिससे प्रतियोगिता और भी रोमांचक हो गई। कई टीमों ने प्रयास किया, लेकिन अंततः एक टीम ने शानदार तालमेल और साहस दिखाते हुए मटकी फोड़ दी। मटकी फूटते ही चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट और होली के जयकारों से माहौल गूंज उठा।

आयोजकों की ओर से विजेता टीम को 5100 रुपये का नकद पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को भी होली की शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बिरहाना रोड और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन को देखने पहुंचे। रंग-बिरंगे गुलाल, पिचकारियों और संगीत की धुनों के बीच लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयां देते नजर आए। युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग और बच्चे भी इस उत्सव में बढ़-चढ़कर शामिल हुए।

संगठन के अध्यक्ष गणेश बाजपेई ने बताया कि बिरहाना रोड नवयुवक संघ 27 वर्षों से इस तरह के सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। इसका उद्देश्य शहर में आपसी भाईचारा, उत्साह और परंपराओं को जीवित रखना है। उन्होंने कहा कि हर साल इस आयोजन में लोगों की संख्या और उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिरहाना रोड की होली अब कानपुर की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध होली के रूप में पहचानी जाने लगी है। यहां का रंग, उत्साह और सामूहिक भागीदारी इस उत्सव को खास बना देती है।

पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। रंग, संगीत और उत्साह से भरे इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानपुर की होली अपने अनोखे अंदाज और भव्यता के लिए जानी जाती है।

रूरा में फौजी विवेक यादव गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे

चुनावी जंग की खुन्नस में फौजी कुर्बान

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। तिगाईं जिला पंचायत सीट को लेकर चल रही सियासी खींचतान अब पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। पेट्रोल पंप पर कथित तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग के आरोपों में रूरा पुलिस ने सेना के जवान विवेक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि क्षेत्र में इस पूरे घटनाक्रम को आगामी जिला पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और राजनीतिक दबाव की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

मामला रूरा थाना क्षेत्र के तिगाईं गांव का है। गांव निवासी शुभम शुक्ला ने 5 मार्च को रूरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 4 मार्च की शाम उनके परिवार के पेट्रोल पंप एसडी फिलिंग स्टेशन तिगाईं पर कई लोग एक साथ पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ की। आरोप है कि इस दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन लालू सिंह गौर को धमकाते हुए बिक्री के 1370 रुपये छीन लिए गए। घटना के बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

वादी के अनुसार, इसके बाद आरोपी गांव तिगाईं में पहुंचे और वहां भी गाली-गलौज की। आरोप लगाया गया कि इसी दौरान फौजी ने तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद रविवार को अहिरन गढ़ेवा स्कूल के पास से फौजी विवेक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुधीर भारद्वाज के अनुसार प्रारंभिक विवेचना में लूट की घटना सही नहीं पाई गई, जिसके चलते लूट की धारा हटा दी गई है। फिलहाल अन्य आरोपों की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- तिगाईं जिला पंचायत सीट की सियासत गरमाई, फौजी पर कानूनी शिकंजा
- पेट्रोल पंप पर कथित तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में हुई गिरफ्तारी
- पहले मुकदमे में जोड़ी गई लूट की धारा बाद में हटाई गई
- चुनावी रंजिश के आरोपों से मामला हुआ राजनीतिक

जिला पंचायत सीट की सियासत में उलझा मामला

तिगाईं जिला पंचायत सीट को लेकर क्षेत्र में पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार आगामी चुनाव को लेकर कई संभावित उम्मीदवार अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि फौजी विवेक यादव अपने पिता चंद्रपाल यादव को जिला पंचायत चुनाव में उतारने की रणनीति बना रहे थे। दूसरी ओर वादी शुभम शुक्ला भी उसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस मुकदमे को लेकर क्षेत्र में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से विवाद ने आपराधिक रूप ले लिया है। फौजी के समर्थकों का आरोप है कि चुनावी माहौल को देखते हुए उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है और मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वही स्थानी लोगों का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख आशीष मिश्रा से मिलीभगत कर शुभम शुक्ला सिंडिकेट चलाता है. ठेकेदारी हो चाहे खनन हो या अन्य कोई भी गतिविधियां इसमें यह लोग पूरी तरह से शामिल रहते हैं.

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

मुकदमे में शुरुआत में लूट जैसी गंभीर धारा जोड़े जाने और बाद में उसे हटाए जाने से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि लूट की घटना सही नहीं थी तो इतनी गंभीर धारा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको लेकर क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया था और विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आए, उसी के अनुसार धाराओं में संशोधन किया गया है।

पहले से भी दर्ज हैं कई मुकदमे

पुलिस सूत्रों के अनुसार विवेक यादव के खिलाफ पहले से भी रूरा और अकबरपुर थानों में मारपीट और विवाद से जुड़े कई मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले ने तिगाईं क्षेत्र की सियासत को गरमा दिया है। जहां एक ओर गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों में नाराजगी है, वहीं दूसरी ओर विरोधी पक्ष इसे कानून की कार्रवाई बता रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष विवेचना जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ

पश्चिम बंगाल में आयोजित इंटरनैशनल संथाल कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे से जुड़ा विवाद केवल कार्यक्रम में व्यवस्था तक सीमित नहीं। यह मामला अब संवैधानिक गरिमा, प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी राजनीति का बन चुका है। राष्ट्रपति का खुद सार्वजनिक रूप से खामियों की ओर इशारा करना भी सामान्य बात नहीं है।

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कार्यक्रम स्थल आखिरी समय में बदल दिया गया। स्थानीय प्रशासन का तर्क था कि मूल स्थान भीड़भाड़ वाला था। लेकिन, राष्ट्रपति ने खुद उस स्थान का दौरा किया और कहा कि जगह पर्याप्त थी। इसके अलावा प्रोटोकॉल के उल्लंघन और दूसरी लापरवाही की बात भी कही जा रही है।

भारत में राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर माना जाता है। केंद्र और राज्यों में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यक्रम कभी किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ता। यह पद किसी व्यक्ति की नहीं, देश की गरिमा और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति खुद यह महसूस करती हैं कि उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया, तो कई सवाल खड़े होते हैं।

राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को लेकर सख्त नियम है, जिनका पालन हर हाल में करना होता है। राष्ट्रपति को आमतौर पर राज्य के मुख्यमंत्री रिसीव करते हैं या उनकी तरफ से नॉमिनेट उनका कोई मिनिस्टर। बताया जा रहा है कि बंगाल में ऐसा नहीं हुआ।

केंद्र सरकार ने इस चुक पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन, इस घटना से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वह है पश्चिम बंगाल की राजनीति। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्य टक्कर BJP व सत्ताधारी TMC के बीच मानी जा रही।चुनावी मैदान की यही तल्खी अब संवैधानिक परंपराओं में दिख रही है। TMC ने केंद्र पर राष्ट्रपति पद के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई प्रोटोकॉल नहीं टूटा। यह कार्यक्रम संथाल आदिवासियों से जुड़ा था। राष्ट्रपति खुद इस समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन, अब ध्यान मुख्य मुद्दे से हटकर इस विवाद की ओर चला गया। इस मामले से यह भी पता चलता है कि देश में कई बार बड़े आयोजनों तक की तैयारी आखिरी वक्त तक चलती रहती है। अगर राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े सारे इंतजाम पहले ही पूरे होते, तो शायद यह विवाद खड़ा ही नहीं होता।

भारत में आईटी का महाकुम्भ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल रहा डिजिटल भविष्य, तकनीकी क्रांति के नए दौर में भारत बन रहा वैश्विक नवाचार का केंद्र

✍ निखिलेश मिश्रा
(साइबर एक्सपर्ट एवं पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी)

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र आज एक नए ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। पिछले तीन दशकों में भारत ने दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर सेवाओं और तकनीकी समाधान प्रदान करके एक मजबूत पहचान बनाई है लेकिन अब देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ढ्ढ), क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक नए तकनीकी युग में प्रवेश कर रहा है।मेरे जैसे अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन भारत को विश्व की अग्रणी तकनीकी शक्तियों में शामिल कर सकता है।

दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रही है और भारत इस तकनीकी क्रांति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। भारतीय आईटी कंपनियाँ अब केवल सॉफ्टवेयर सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एआई आधारित समाधान विकसित कर रही हैं जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, कृषि और सरकारी सेवाओं में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। इससे कार्यप्रणाली तेज़, सटीक और अधिक प्रभावी बन रही है।

भारत में हजारों इंजीनियर और शोधकर्ता एआई और मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं, जिससे देश की तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ रही है।

डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के साथ भारत में डेटा सेंटर उद्योग भी अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और डिजिटल भुगतान की लोकप्रियता के कारण डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ रही है।

इस डेटा को सुरक्षित रखने और प्रोसेस करने के लिए देश के प्रमुख शहरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है भारत में तकनीकी विकास को गति देने के लिए कई बड़े उद्योग समूह भी आगे आ रहे हैं। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अम्बानी और गौतम अडानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की योजनाएँ बना रहे हैं।

इन निवेशों से भारत में नई तकनीकी परियोजनाएँ शुरू होंगी, जिससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश का तकनीकी ढांचा मजबूत होगा।

भारत की युवा आबादी इस तकनीकी क्रांति की सबसे बड़ी ताकत है। आईटी क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।

इसके साथ ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से विकसित हो रहा है। कई भारतीय स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं और नई तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

आज दुनिया की कई प्रमुख तकनीकी कंपनियाँ अपने अनुसंधान और विकास केंद्र भारत में स्थापित कर रही हैं। इसका मुख्य कारण है भारत की प्रतिभाशाली मानव संसाधन, मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा और तेजी से बढ़ता डिजिटल बाजार।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत केवल आईटी सेवाओं का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह तकनीकी नवाचार और डिजिटल समाधान का वैश्विक केंद्र बन सकता है। भारत का आईटी उद्योग तेजी से एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर जैसी उन्नत तकनीकों के साथ देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

यदि यही विकास की गति बनी रही, तो आने वाले समय में भारत दुनिया की प्रमुख तकनीकी शक्तियों में शामिल हो सकता है और वैश्विक डिजिटल भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

श्रावस्ती कांड से मिलती है चेतावनी

किसान राजनीति के नाम पर पनपती अराजकता

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सामने आया किसान नेता आंचल मिश्रा हत्याकांड केवल एक महिला की निर्मम हत्या भर नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और तथाकथित किसान राजनीति के भीतर पनप रही कई खतरनाक प्रवृत्तियों को उजागर करने वाला गंभीर मामला है। यह घटना उन सवालों को भी सामने लाती है जिन पर अब खुलकर चर्चा होना आवश्यक हो गया है।

आंचल मिश्रा भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की महिला विंग की जिलाध्यक्ष बताई जा रही थी। 17 फरवरी 2026 को वह किसान यूनियन की बैठक में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। कई दिनों की तलाश और जांच के बाद ककरदरी रेंज के घने जंगलों से जो मिला वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था – क्षत-विक्षत कंकाल, जली हुई साड़ियां, टूटी चूड़ियां और एक भयावह अपराध की कहानी।

पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने इस पूरे मामले को और भी चिंताजनक बना दिया। जानकारी के अनुसार आंचल मिश्रा का संबंध सूरज वर्मा नाम के एक हिस्ट्रीशीटर से था। अवैध संबंधों, पैसों के लेन-देन और ब्लैकमेलिंग के विवाद ने अंततः इस रिश्ते को हिंसा में बदल दिया। आरोप है कि इसी विवाद के चलते आरोपी ने जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया।

यह घटना केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं है, बल्कि उस व्यापक समस्या की ओर संकेत करती है जो आज किसान संगठनों के नाम पर तेजी से फैल रही है। देश में किसानों की समस्याओं को उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बने संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लेकिन जब ऐसे संगठनों में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ बढ़ जाती है, तो उनका उद्देश्य ही संदिग्ध हो जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न नामों से किसान यूनियनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इनमें से कई संगठन वास्तव में किसानों के हितों के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अनेक स्थानों पर इन संगठनों का इस्तेमाल दबंगई, निजी स्वार्थ और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के साधन के रूप में भी किया जा रहा है।

कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग सिर पर हरा गमछा बांधकर या गाड़ियों पर किसान यूनियन के स्टीकर लगाकर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इससे वास्तविक किसानों की छवि भी प्रभावित होती है और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

श्रावस्ती की यह घटना एक और गंभीर पहलू की ओर भी ध्यान दिलाती है। विभिन्न संगठनों में महिला विंग का गठन महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि इन मंचों का उपयोग निजी स्वार्थ, शोषण या अनैतिक गतिविधियों के लिए होने लगे तो यह समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति बन जाती है। इसलिए यह समय आत्ममंथन का है।

किसान संगठनों को भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी होगी। सरकार और प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी संगठन के नाम पर कानून से ऊपर होने की मानसिकता को बढ़ावा न मिले।

किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। "अन्नदाता" की यह पहचान अत्यंत पवित्र और सम्मानित है। इसलिए आवश्यक है कि इस नाम का उपयोग करने वाले संगठन भी उसी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।श्रावस्ती का यह कांड एक दर्दनाक घटना जरूर है, लेकिन यदि इससे समाज और व्यवस्था को आत्ममंथन की प्रेरणा मिलती है तो शायद भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सकेगा।

✍ अनूप अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार

बिल्हौर बस स्टैंड के लिए रास्ता साफ, भूमि की पैमाइश कर शासन को भेजी रिपोर्ट

पापा होटल के समीप सरकारी राशन की दुकान के पास बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित

रिजवान कुरैशी/ स्वराज इंडिया

बिल्हौर (कानपुर)। कस्बे में लंबे समय से लंबित बस स्टैंड की समस्या के समाधान की दिशा में अब प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। स्थायी बस स्टैंड के निर्माण के लिए पापा होटल के समीप बनी सरकारी राशन की दुकान के पास भूमि चिन्हित कर उसकी पैमाइश कर ली गई है और एसडीएम ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

- एसडीएम ने कराई पैमाइश, शासन को भेजी रिपोर्ट
- बस स्टॉप बनने के बाद ज्यादातर बसें कस्बे के अंदर से होकर चलेंगी
- स्वराज इंडिया अखबार ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था

बिल्हौर कस्बे में बस स्टैंड न होने के कारण यात्रियों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अधिकांश रोडवेज और प्राइवेट बसें कस्बे के अंदर आए बिना ही बाईपास से गुजर जाती थीं, जिससे यात्रियों को बस पकड़ने के लिए दूर जाना पड़ता था।

कानपुर के रावतपुर से बिल्हौर आने वाले यात्रियों को भी काफी दिक्कत होती थी। ज्यादातर बस चालक यात्रियों को पहले ही बता देते थे कि बस बिल्हौर बाईपास से होकर जाएगी। ऐसे में यात्रियों को बाईपास पर उतरना पड़ता था और वहां से कस्बे तक आने के लिए उन्हें ई-रिक्शा या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता था।

बस स्टॉप बनने के बाद अब ज्यादातर बसें कस्बे के अंदर से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को सीधे कस्बे में ही बस की सुविधा मिल सकेगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस समस्या को आपके अपने स्वराज इंडिया अखबार ने समय-समय पर प्रमुखता से उठाया था। क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने भी इस समस्या पर परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर बस स्टैंड निर्माण की मांग की थी। विधायक के पत्र के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और संभावित स्थानों की तलाश शुरू की गई।

जीटी रोड किराने परिवहन निगम के बस अड्डे के लिए प्रस्तावित भूमि।

इसी क्रम में एसडीएम संजीव दीक्षित ने क्षेत्रीय लेखपाल ललित और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया और उसकी पैमाइश कराकर रिपोर्ट शासन को भेज दी। अब शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। स्थायी बस स्टैंड बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और कस्बे में लंबे समय से बनी अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था में भी सुधार होने की उम्मीद है।

बसपा की बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर

नौशाद अली बोले– बूथ स्तर पर भाईचारा मजबूत कर 2027 में सरकार बनाने का लक्ष्य

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। बहुजन समाज पार्टी के 'चलो बूथ की ओर' अभियान के तहत सोमवार को बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के चौबाली गांव में सेक्टर स्तर की बैठक आयोजित की गई। देवहा सेक्टर के बूथ संख्या 73 और 74 की बैठक प्रदीप बौद्ध के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य मंडल प्रभारी व पूर्व एमएलसी नौशाद अली ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा की सरकार बनाने के लिए अभी से जुट जाएं। उन्होंने 15 मार्च को बसपा, बामसेफ और डीएस - 4 के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के जन्मदिन पर लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। बैठक में देवहा सेक्टर से प्रदीप बौद्ध और नानामऊ सेक्टर से वीनू उर्फ विनय गौतम को सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विशिष्ट अतिथि विधान सभा प्रभारी रामशंकर कुरील ने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस दौरान विधानसभा प्रभारी एडवोकेट विनय कुमार गौतम, विधानसभा अध्यक्ष रमेश पाल, पूर्व बसपा प्रत्याशी जीवनलाल भारती, उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र बौद्ध, महासचिव मनोज कुमार कमल, सचिव रामदास कठेरिया समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में बूथ गठन का कार्य भी किया गया।

बसपा बैठक में मौजूद पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

खेत के कुएं में मिला लापता किसान का शव, परिवार में मचा कोहराम

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर थाना क्षेत्र के महिगवां गांव में लापता चल रहे एक किसान का शव सोमवार को कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। महिगवां गांव निवासी करीब 50 वर्षीय महाराज सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय जय नारायण सिंह यादव खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी रजनी, तीन बेटियां कल्पना, मोहिनी और रानी के साथ एक बेटा छोड़ है। बताया जा रहा है कि महाराज सिंह रविवार को रोज की तरह अपने खेतों की ओर गए थे, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटे। देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने गांव व आसपास के इलाकों में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका।

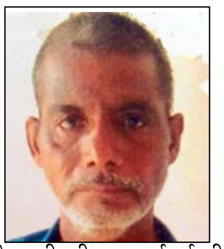

इसके बाद परिजन पूरी रात परेशान रहे। सोमवार उनकी पत्नी और बेटियां फिर से खेतों की ओर उन्हें ढूंढने पहुंचीं। इस दौरान जब उन्होंने खेत में बने कुएं में झांककर देखा तो अंदर महाराज सिंह का शव पड़ा दिखाई दिया। यह दृश्य देखते ही परिजनों के होश उड़ गए और चीख-पुकार मच गई।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। सूचना पर बिल्हौर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला कुएं में गिरने से हुई मौत का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि अगर परिजनों की ओर से कोई तहरीर दी जाती है तो उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों को मिलेगी पशु उपचार की सुविधा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर (कानपुर)। तरीपाठकपुर गांव में पशुपालकों को जल्द ही पशु उपचार की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यहां पशु सेवा केंद्र के निर्माण के लिए 17 लाख रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। सोमवार को राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर केंद्र के लिए चिन्हित जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। अधिकारियों के अनुसार जमीन खाली होने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो करीब छह महीने के भीतर पशु सेवा केंद्र का भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इससे क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2007-08 में ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 131 की करीब 0.510 हेक्टेयर भूमि को तत्कालीन ग्राम प्रधान शिवराज भास्कर ने पशुपालन विभाग के लिए प्रस्तावित किया था। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम गठित की गई थी। सोमवार को नायब तहसीलदार दिव्या भारती के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक विजय प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक मुकेश दुबे, लेखपाल और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया।

नायब तहसीलदार ने बताया कि पशुपालन विभाग के लिए चिन्हित भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। बजट जारी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

जर्जर उपनिबंधक कार्यालय का एआईजी स्टाम्प ने किया निरीक्षण

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। जर्जर हो चुके उपनिबंधक (रजिस्ट्री) कार्यालय भवन का सोमवार को एआईजी स्टाम्प ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों के साथ आसपास की जमीन भी देखी गई, ताकि वर्तमान स्थान के पास ही नए कार्यालय भवन के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा सकें।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम बिल्हौर संजीव दीक्षित, उपनिबंधक इरशाद अहमद, नायब तहसीलदार सीपी राजपूत और लेखपाल ललित रजक मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि उपनिबंधक कार्यालय के लिए जमीन आवंटित होने के बाद ही नए भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। मालूम हो कि पहले शासन की ओर से रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए कई करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया गया था और निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया था। लेकिन तहसील से दूर सुभान पुर गांव के पास ऋाइम बहुल क्षेत्र में नया कार्यालय बनाए जाने के

विरोध में वकीलों ने आंदोलन शुरू कर दिया था।

वकीलों ने कई दिनों तक रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बाद में अधिकारियों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद नई जगह पर हो रहा निर्माण कार्य रोक दिया गया था। अब विभाग की ओर से मौजूदा स्थान के पास ही जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर ब्रेक अब चुनावी नतीजों के बाद ही फैसला

पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के चुनाव में व्यस्त भाजपा नेतृत्व, होली के आसपास विस्तार की अटकलें ठंडी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में चल रहा योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। सत्ता के गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे थे कि होली के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के चलते पार्टी नेतृत्व ने इस पर फिलहाल विराम लगा दिया है। इससे मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे कई विधायकों को अब और इंतजार करना पड़ सकता है।

भाजपा के सूत्रों के मुताबिक इस समय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में व्यस्त है। इन राज्यों में पार्टी की रणनीति और चुनावी अभियान पर पूरा फोकस रखा जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल ने भी केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में संगठन के स्तर पर यह राय बनी है कि इन महत्वपूर्ण चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार करना फिलहाल रणनीतिक रूप से उचित नहीं होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार मई 2026 या उसके बाद तक टल सकता है। दरअसल, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बेहद सावधानी से कदम उठाना चाहते हैं, ताकि आगामी चुनावी रणनीति को मजबूती मिल सके।

गौरतलब है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत 25 मार्च 2022 को 53 मंत्रियों के साथ हुई थी। बाद में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में मंत्री बनने और राज्यमंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद चुने जाने के बाद मंत्रिमंडल में कुछ पद रिक्त हो गए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से अभी भी करीब 9 से 10 पद खाली हैं।

सूत्रों के अनुसार जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें नए चेहरों को मौका देने के साथ कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है। फिलहाल मंत्री पद की दौड़ में शामिल विधायकों को चुनावी नतीजों के बाद तक इंतजार करना होगा।

मंत्रिमंडल विस्तार क्यों टला?

- भाजपा नेतृत्व पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त
- बिहार की सियासी हलचल ने बढ़ाई प्राथमिकता
- 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक तैयारी
- जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश

बुंदेलखंड के निनावली जागीर सरकार के हरिहर मनींद्र भी शंकराचार्य के साथ

स्वराज इंडिया ब्यूरो

जालौन। जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज द्वारा बुधवार को लखनऊ में गौ माता, सवर्णों, संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम में जालौन के निनावली जागीर सरकार के श्रीहरिहर मणीन्द् जी महाराज ने अपना समर्थन दिया है।

हरिहर मणीन्द् जी महाराज का कहना है कि पूरा बुंदेलखंड शंकराचार्य भगवान के साथ है। उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज को दिशा देते हैं और जब समाज भटक जाता है तो उसे सुधारने का काम भी संतों का है। उन्होंने बताया कि अस्वस्थतावश कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन उनके सारे शिष्य लखनऊ पहुंच रहे हैं।

11 माह से मनेरगा कर्मियों को नहीं मिला मानदेय, परिवार भुखमरी की कगार पर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

फर्रुखाबाद। जनपद में कार्यरत मनरेगा कर्मियों को 11 माह के लंबे समय से मानदेय और ईपीएफ का भुगतान न होने से परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। कर्मियों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज को इसी तरह उठाते रहेंगे द्य कर्मियों में शासन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्याप्त है। उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ग्राम रोजगार सेवक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों ने प्रशासन से जल्द भुगतान कराने की मांग उठाई है।

कर्मचारियों ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं उपायुक्त श्रम एवं रोजगार को संबोधित पत्र में कहा है कि जनपद में मनरेगा योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है। साथ ही विभागीय निर्देशों के अनुसार सभी योजनाओं को सफल बनाने में कर्मियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर, क्रॉप सर्वे सहित कई विभागीय कार्यों में भी मनरेगा कर्मियों ने अपना सक्रिय योगदान दिया है। इसके बावजूद विभागीय शिथिलता के चलते मई 2025 से अब तक मनरेगा कर्मियों का मानदेय नहीं मिला है, जबकि कर्मचारियों के ईपीएफ की देनदारी काफ़ी लंबे समय से लंबित चली आ रही है।

कर्मचारियों का कहना है कि पिछले वर्ष दीपावली पर भी उन्हें वेतन नहीं मिला और अब होली जैसे बड़े त्योहार पर भी भुगतान न होने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट के साथ ही साथ ब्याज पर रुपया लेकर खर्च कर लिया और परिवार भी भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि लगातार मानदेय न मिलने के कारण उनके सामने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है, जिससे वे मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में मानदेय न मिलने के कारण मनरेगा कर्मियों के साथ गंभीर घटनाएं होने के मामले सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इस स्थिति को संविधान के अनुच्छेद-21 में वर्णित जीवन के अधिकार के विपरीत बताया है।

संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस संबंध में 23 फरवरी 2026 को रोजगार गारंटी आयुक्त से मिलकर भी समस्या से अवगत कराया गया था। प्रदेश में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना की गई है। कर्मियों का कहना है कि जब मानव दिवस का सृजन अधिक हुआ है तो प्रशासनिक मद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को समय पर मानदेय और ईपीएफ का भुगतान न होना वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जनपद के सभी मनरेगा कर्मियों का लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 17 मार्च 2026 को जनपद के समस्त मनरेगा कर्मचारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराएंगे।इस दौरान विकासखंड राजेपुर के कई मनरेगा कर्मियों ने पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रशासन से शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।

सन्दलपुर में युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस नहीं लिख रही रिपोर्ट

पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार, सिर में गंभीर चोट के बाद हालत बिगड़ी

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के सन्दलपुर में एक युवक पर कथित रूप से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते उसे बेरहमी से पीटा और अवैध असलहे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान कर मामला दबाने की कोशिश की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सन्दलपुर निवासी काला राम पुत्र लालाराम ने पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 02 मार्च 2026 को शाम लगभग 3-4 बजे वह घरेलू सामान खरीदने के लिए सन्दलपुर बाजार जा रहा था। इसी दौरान सन्दलपुर चौराहे पर पहले से मौजूद राकेश उर्फ कालीघटा पुत्र सोनेलाल, उसके बेटे शमीर और सनि, तथा जुबैर अहमद व उवैश अहमद उर्फ शानू पुत्र जलीश अहमद ने उसे घेर लिया।

पीड़ित के अनुसार सभी लोग शराब के नशे में थे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि उवैश अहमद उर्फ शानू ने तमंचा जैसे अवैध असलहे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के दौरान शोर सुनकर जफर, अमर सिंह, सलमान और गौरव सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी पीड़ित को मृत समझकर मौके से फरार हो गए। इसी बीच किसी ने सन्दलपुर चौकी पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पीड़ित का कहना है कि गांव के लोग उसे घायल अवस्था में थाना मंगलपुर लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने न तो उसका मेडिकल कराया और न ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उल्टा पुलिस ने पीड़ित और आरोपी राकेश उर्फ कालीघटा का शांति भंग में चालान कर दिया। काला राम ने बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, जिससे चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही है। पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने, मेडिकल जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद अब पूरे मामले की जांच और कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

जमवाय माता मंदिर में कल होगा विशाल भंडारा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। विकास खंड मलासा के मलासा गांव में स्थित प्रसिद्ध जमवाय माता मंदिर में बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों के क्रम में यह भंडारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

मंदिर परिसर में पिछले कुछ दिनों से धार्मिक माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु माता के दर्शन करने के साथ ही पूजा-अर्चना कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं। भंडारे के आयोजन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों के अनुसार भंडारे में दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भंडारे की शुरुआत होगी, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों ने क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर माता के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। माना जा रहा है कि भंडारे में आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु भी शामिल होंगे, जिससे मंदिर परिसर में पूरे दिन धार्मिक और भक्ति का माहौल बना रहेगा।

सुबह सड़कों पर कोहरे जैसी धुंध

रसूलाबाद रूरा सहित अन्य क्षेत्र में 10 बजे तक छाई रही धुंध, मास्क लगाकर निकले लोग

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

रसूलाबाद, कानपुर देहात। मार्च में जहां गर्मी धीरे-धीरे दस्तक देने लगी है, वहीं मंगलवार सुबह रसूलाबाद क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह के समय घना कोहरा छा जाने से लोगों को एक बार फिर सर्दियों जैसा अहसास हुआ। सड़कों, खेतों और बाजारों में घनी धुंध के कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सुबह करीब छह बजे से आठ बजे के बीच कोहरा सबसे अधिक घना रहा, जिससे दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया। मुख्य मार्गों पर चलने वाले वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाना पड़ा।

कई स्थानों पर लोग सावधानी बरतते हुए अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दिए। कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास धुंध की मोटी परत साफ नजर आ रही थी।

कोहरे के कारण सुबह के समय वातावरण में हल्की ठंडक भी महसूस की गई। इससे लोगों को कुछ देर के लिए सर्दियों जैसा माहौल लगने लगा। एहतियात के तौर पर कई लोग मास्क लगाकर घरों से बाहर निकले, ताकि धुंध और ठंडी हवा से बचाव किया जा सके

किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है नमी

स्थानीय किसानों का कहना है कि मार्च के महीने में आमतौर पर सुबह का मौसम साफ रहने लगता है, लेकिन इस बार अचानक कोहरा छाने से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। हालांकि किसानों का मानना है कि सुबह की हल्की नमी गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों ने बताई वजह

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मार्च के शुरुआती दिनों में दिन के समय तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन रात के समय तापमान अपेक्षाकृत कम रहने और हवा में नमी अधिक होने के कारण सुबह के समय कोहरा बन जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में होली के बाद भी कभी-कभी ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। करीब नौ बजे के बाद सूरज की किरणें तेज होने लगीं, जिससे धीरे-धीरे कोहरा छंट गया। लगभग 10 बजे तक धुंध पूरी तरह खत्म हो गई और इसके बाद मौसम साफ होने के साथ क्षेत्र में जनजीवन सामान्य रूप से चलने लगा।

19 माह से मानदेय नहीं, आर्थिक संकट से जूझ रहे रोजगार सेवक

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- राजपुर ब्लॉक के ग्राम रोजगार सेवकों ने बीडीओ के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन,
- ईपीएफ भुगतान की भी उठाई मांग

कानपुर देहात। राजपुर ब्लॉक के ग्राम रोजगार सेवकों ने लंबे समय से लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान को लेकर सोमवार को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के बैनर तले दिए गए इस ज्ञापन में रोजगार सेवकों ने अपनी आर्थिक समस्याओं और कार्य से जुड़ी परेशानियों को प्रमुखता से उठाया।

ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पाल के नेतृत्व में रोजगार सेवक बड़ी संख्या में ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि पिछले 19 महीनों से ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय लंबित पड़ा हुआ है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नियमित आय न होने के कारण परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है।

सुरेंद्र कुमार पाल ने बताया कि रोजगार सेवकों से उनकी स्वयं की ग्राम पंचायत के साथ-साथ अन्य रिक्त ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त कार्य भी लिया जा रहा है, जबकि यह व्यवस्था नियमों के विपरीत है।

अतिरिक्त कार्य करने के बावजूद मानदेय का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा, जिससे रोजगार सेवकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी ग्राम रोजगार सेवकों का 19 माह से लंबित मानदेय तत्काल जारी किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की समयावधि समाप्त होने से पहले सभी रोजगार सेवकों का मानदेय और ईपीएफ की धनराशि उनके यूएएन खातों में स्थानांतरित की जाए, ताकि भविष्य में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इस संबंध में खंड विकास अधिकारी राजपुर हरगोविंद गुप्ता ने बताया कि रोजगार सेवकों द्वारा दिया गया मांग पत्र जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और शासन स्तर पर उनकी मांगों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान विजय सिंह, संजय सिंह, हरनारायण, कमलेश कुमारी, राकेश बाबू, जितेंद्र सिंह, अंबुज कुमार, सपना, प्रमोद कुमार, रामगोविंद, आशीष कुमार, मंजू देवी, रामसिंह, नीरज कुमार, अमरेश बाबू, सीमा देवी, कालिंदी और मुन्नी लाल सहित कई ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।

अलग-अलग सड़क हादसों में चार घायल दो की हालत गंभीर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो।

कानपुर देहात। थाना क्षेत्र में देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। दोनों घटनाओं में दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसों की सूचना मिलने पर पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।

पहला हादसा राजपुर थाना क्षेत्र के खासबरा गांव के सामने मुगल रोड पर हुआ। यहां भाल गांव निवासी 70 वर्षीय संतराम अपने 28 वर्षीय नाती अनुज सिंह के साथ बाइक से सिकंदरा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। देर रात जब वे खासबरा गांव के सामने पहुंचे, तभी सिकंदरा की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार बाबा-नाती सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पीछे आ रहे गांव के लोगों और राहगीरों ने तत्काल दोनों घायलों को उठाकर राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया।

ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. हरदीप सिंह ने बताया कि बुजुर्ग संतराम को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि उनके नाती अनुज का उपचार पीएचसी में ही किया गया।

इसी बीच दूसरा हादसा राजपुर कस्बे के पैलावर मोड़ के पास हुआ। यहां सिकंदरा से राजपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बाइक सवार दंपत्ति 40 वर्षीय सुशीला और उनके 50 वर्षीय पति अनिल को सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक से गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल राजपुर पीएचसी पहुंचाया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया। जांच के दौरान सुशीला की हालत गंभीर पाई गई। डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अकबरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि अनिल का उपचार स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है।

लगातार हो रहे सड़क हादसों से क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्गों पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि दोनों सड़क हादसों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित वाहनों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की है।

कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर निस्तारण का दिया आश्वासन

स्वराज इंडिया ब्यूरो

- सपा नेता वीरसेन यादव का सत्तारूढ़ सरकार पर प्रहार

कानपुर देहात माती । आज कार्यक्रम के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के प्रांतीय नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव का मूसानगर आगमन हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री यादव ने प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए उसे जनभावनाओं की उपेक्षा करने वाली शासन व्यवस्था करार दिया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्ता तंत्र में समाज का प्रत्येक वर्ग अपने को उपेक्षित, पीड़ित और अपमानित अनुभव कर रहा है। सरकार की नीतियां जनकल्याण से विमुख होकर केवल औपचारिक घोषणाओं और खोखले आश्वासनों तक सीमित हो गई हैं। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों, गरीबों तथा नौजवानों के हितों की निरंतर अवहेलना की जा रही है, जिससे व्यापक असंतोष और निराशा का वातावरण व्याप्त हो चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का अन्नदाता आज गहन आर्थिक एवं प्रशासनिक संकट से जूझ रहा है। किसानों को उनकी उपज का समुचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, समय पर उर्वरक की उपलब्धता न होने से खेती-किसानी प्रभावित हो रही है, वहीं सिंचाई के लिए पर्याप्त जलापूर्ति भी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश का युवा वर्ग बेरोजगारी की विकराल समस्या से ग्रस्त है, किंतु सरकार रोजगार सृजन के प्रति घोर उदासीनता का परिचय दे रही है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर संवाद स्थापित कर उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर उनका स्वागत करने वालों में समाजवादी पार्टी कानपुर देहात के जिला सचिव रामविलास निषाद, बसंत गुप्ता, कैप्टन रामशंकर प्रजापति, आलोक गुप्ता, सपा पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष सुजीत पाल, ग्राम प्रधान बलवान सिंह यादव, सहकारी संघ मूसानगर के पूर्व अध्यक्ष कैलाश सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मलखान सिंह, लाखन सिंह यादव, कुलदीप सिंह, मोनू यादव, लाली सक्सेना, बृजेश गौतम, मोहित गुप्ता सहित अनेक गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डीएम के मुआयने के बाद तहसील में बड़ी कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

रसूलाबाद, कानपुर देहात। जिलाधिकारी के हालिया औचक निरीक्षण के बाद रसूलाबाद तहसील में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। निरीक्षण के बाद दो कर्मचारियों पर गाज गिराते हुए प्रशासन ने एसडीएम पेशकार और रजिस्ट्रार कानूनगो का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। वहीं पेशकार के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक आदेश के अनुसार एसडीएम पेशकार संजीव दुबे का स्थानांतरण डेरापुर तहसील कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रार कानूनगो आर.के. महेंद्र को सिकंदरा तहसील भेजा गया है। इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया और पूरे दिन इस फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा।

सूत्रों के मुताबिक हाल ही में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने रसूलाबाद तहसील का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों की

- एसडीएम पेशकार व रजिस्ट्रार कानूनगो का तबादला, पेशकार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश
- लंबे समय से जमे कर्मचारियों पर डीएम की टेढ़ी नजर, छह वर्ष से रसूलाबाद में तैनात थे पेशकार

कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। इसी दौरान कुछ अनियमितताएं और कार्य में लापरवाही सामने आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

बताया जा रहा है कि पेशकार संजीव दुबे करीब छह वर्षों से रसूलाबाद तहसील में तैनात थे। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों को लेकर जिलाधिकारी पहले से ही सख्त रुख अपनाए हुए थे। ऐसे में निरीक्षण के बाद की गई इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।

विभागीय जांच के बाद हो सकती है कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी के निर्देश पर पेशकार संजीव दुबे के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी की निगाह अब लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अन्य कर्मचारियों पर भी बनी हुई है।

कार्रवाई से सुधरने की उम्मीद

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से तहसील की कार्यप्रणाली में सुधार आने की उम्मीद है। लोगों का मानना है कि समय-समय पर इस तरह के निरीक्षण और कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे आम जनता को भी राहत मिलेगी

तहसील में बढ़ी हलचल, कर्मचारी हुए सतर्क

डीएम की इस सख्त कार्रवाई के बाद रसूलाबाद तहसील में कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। कर्मचारी अब अपने कार्यों को लेकर अधिक सतर्क दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

तरावीह मुकम्मल होने पर बना रूहानी माहौल

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात माती। पवित्र रमजान माह के दौरान कस्बा गजनेर की बाजार स्थित मस्जिद में देर रात तरावीह की नमाज़ के दौरान कुरआन पाक मुकम्मल होने पर अत्यंत आध्यात्मिक और श्रद्धामय वातावरण व्याप्त हो गया। मुकम्मल होने की इस मुबारक घड़ी में कुरआन शरीफ सुनाने वाले हाफिज शकील को उपस्थित जनसमूह द्वारा सम्मानपूर्वक इनामात से नवाजा गया।

कार्यक्रम के दौरान कचहरी वाली मस्जिद के इमाम आफताब शाहब ने प्रभावशाली तकरीर एवं भावपूर्ण नात पेश कर उपस्थित लोगों को रमजान की फजीलत और कुरआन के पैगाम से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रोज़ा इबादत, सब्र और आत्मशुद्धि का प्रतीक है तथा कुरआन की तिलावत और उसके सिद्धांतों पर अमल करने से इंसान की दुनियावी और आखिरत की तमाम मुश्किलात सरल हो जाती हैं। इस अवसर पर उन्होंने मुल्क की तरक्की, अमन-चैन तथा बीमारों के स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष दुआ भी कराई।

इस पावन अवसर पर ग्राम प्रधान पति मो. फिरोज ने हाफिज शकील को माला पहनाकर तथा नजराना भेंट कर सम्मानित किया और उनकी खिदमत की सराहना करते हुए हौसला-अफजाई की। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अबू बक्स, मुमताज मंसूरी, कासिम प्रधान सैंथा, नफीस अली, रसूल बक्स, बब्लू

- हाफिज शकील का सम्मान फिरोज ने नजराना देकर की विदाई

मंसूरी, मो. जकी, पप्पू पठान, हाफिज आफताब, हबीब, फारूख, शहीद मेंबर, जाबिर राईन, अशरूज्जमा, रिजवान मंसूरी, अमन, चांद, इदरीश मंसूरी, गुड्डू भाई समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

इसी क्रम में ग्राम हरचंदापुर में भी तरावीह के दौरान कुरआन पाक मुकम्मल होने पर आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण रहा। यहां भी ग्राम प्रधान पति मो. फिरोज ने हाफिज को माला पहनाकर और नजराना भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर जमील, सोनू, मो. जैकी, हनीफ, नफीस हाफिज, अमीन मंसूरी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।रमजान की इस मुकद्दस घड़ी में क्षेत्र के दोनों स्थानों पर धार्मिक सौहार्द, भाईचारे और आध्यात्मिक उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला।

ततारपुर में भव्य होली मिलन समारोह, उड़े गुलाल और फूल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। विकास खंड मलासा के ततारपुर गांव में समाजसेविका आदेश कुमारी नायक एवं डीएनटी महासभा के मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक के संयोजन में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान पूरे कार्यक्रम स्थल पर गुलाल और फूलों की वर्षा के बीच होली का उल्लास देखने को मिला।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मलासा ब्लॉक प्रमुख स्वतंत्र पासवान मौजूद रहे। इसके साथ ही डीएनटी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह नायक भी कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए। आयोजक अर्जुन सिंह नायक ,समाजसेविका आदेश कुमारी नायक ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर तथा अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख स्वतंत्र पासवान ने कहा कि होली जैसे पर्व समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे आयोजनों से लोगों के बीच की दूरियां कम होती हैं और आपसी वैमनस्यता समाप्त

- जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों ने दिया भाईचारे और सौहार्द का संदेश

होती है। उन्होंने सभी से मिलजुल कर त्योहार मनाने और सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की।

वहीं डीएनटी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह नायक ने कहा कि होली भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और सामाजिक पर्व है। यह त्योहार लोगों के दिलों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना पैदा करता है। उन्होंने सभी से पुराने मनमुटाव भुलाकर आपसी भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का कुशल संचालन महेन्द्र पाल ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए और होली के गीत-संगीत व रंगों के बीच उत्साह के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं।

इस अवसर पर समाजसेविका किशोरी त्रिवेदी, स्वदेशी जागरण मंच की जिला सह संयोजिका मीना दीक्षित, डीएनटी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. रमेश सिंह नायक, रामबेटी मंडल उपाध्यक्ष कानपुर, दीपक वर्मा जिला संगठन मंत्री, मुकेश सिंह नायक प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, साहूकार नायक प्रदेश उपाध्यक्ष, पूरन सिंह नायक प्रदेश महामंत्री, प्रधान प्रतिनिधि विकास पाल, पूर्व प्रधान पूरन सिंह नायक, गौतम सिंह नायक, अमन, राजा, आयुष नायक, करन सिंह नायक, मनोज नायक, प्रमोद सिंह नायक, वीरू सिंह नायक, सज्जन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

मानदेय के लिए भटक रहे मनरेगा कर्मी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में गिनी जाने वाली मनरेगा योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले कर्मचारी ही आज अपने मानदेय के लिए परेशान हैं। कई महीनों से भुगतान न मिलने से आक्रोशित मनरेगा कर्मियों ने सोमवार को मलासा ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को ज्ञापन सौंपा और बकाया मानदेय का जल्द भुगतान कराने की मांग की।

कर्मचारियों का कहना है कि मनरेगा योजना के तहत ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक और लेखा सहायक लगातार गांवों में विकास कार्यों का संचालन, निगरानी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

इसके बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण उन्हें लंबे समय से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि जुलाई 2025 से उनका मानदेय लंबित चल रहा है। कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली और होली जैसे बड़े त्योहार भी बिना मानदेय के गुजर गए, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कर्मचारियों का आरोप है कि जब तक काम लेना होता है तब तक विभाग उन्हें जिम्मेदारियों से लाद देता है, लेकिन जब भुगतान की बात आती है तो फाइलें आगे नहीं बढ़तीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योजनाओं को धरातल पर लागू करने वाले कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार अधिकारी कब संवेदनशील होंगे। मनरेगा कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही बकाया मानदेय का भुगतान नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे खंड विकास अधिकारी

संजय कुमार कन्नौजिया ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेजकर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर रिया यादव, अनीता देवी, संतोष कुमार, चंद्रभान, लक्ष्मी देवी, कल्पना देवी, सपना, पिंकी देवी, अर्चना, नंदकिशोर, अंकित सचान, रामकिशोर, सुरेश, शशिकांत, राजेश कुमार, नीरज पाल, रिया कटियार, विजय यादव समेत कई मनरेगा कर्मचारी मौजूद रहे।

फर्रुखाबाद: सातनपुर मंडी में औंधे मुंह गिरे आलू के दाम

❍ किसान खेतों में फेंकने को मजबूर ❍ 200 रुपए कुंतल तक गिरा भाव ❍ सैकड़ों ट्रैक्टर लौटे वापस; आलू का न्यूनतम मूल्य तय करने की उठी मांग

रवि नंदन मिश्रा,स्वराज इंडिया

फर्रुखाबाद। जनपद की प्रसिद्ध सातनपुर आलू मंडी में होली के बाद आलू की रिकॉर्ड आवक से बाजार पूरी तरह चरमरा गया है। मंगलवार को आलू के दाम अचानक गिरकर बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए, जिससे किसानों में भारी निराशा और आक्रोश देखने को मिला। कई किसानों को अपना आलू औने-पौने दाम पर बेचने या मंडी से वापस घर ले जाने की मजबूरी झेलनी पड़ी। कुछ किसान तो आलू मंडी से वापस ले जाकर खेतों में फेंकते हुए भी दिखाई दिए।

मंगलवार सुबह मंडी में आलू का भाव 251 रुपए से 521 रुपए प्रति कुंतल के बीच रहा, जबकि लाल हाइलैंड किस्म का आलू 651 रुपए से 811 रुपए प्रति कुंतल तक बिका। लेकिन जैसे-जैसे मंडी में आलू की आवक बढ़ती गई, कीमतों में तेजी से गिरावट आती गई। दोपहर बाद आलू का भाव गिरकर 201 रुपए से 451 रुपए प्रति कुंतल तक पहुंच गया। कई किसानों ने बताया कि कुछ जगहों पर आलू 200 रुपए कुंतल के आसपास भी बिक रहा है।

मंडी में करीब 250 ट्रक आलू की आवक होने से सुबह से ही ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गईं। देखते ही देखते मंडी परिसर और आसपास की सड़कों पर भारी जाम लग गया। सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रक घंटों तक फंसे रहे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दोपहर के समय मंडी में ट्रकों की एंट्री अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। शाम करीब 4 बजे जब जाम कुछ कम हुआ तब ट्रकों को दोबारा अंदर जाने की अनुमति दी गई। जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहली बार मंडी का दूसरा गेट भी खोलना पड़ा। भाव गिरने की खबर मिलते ही सैकड़ों किसान आलू से भरी ट्रॉलियां लेकर बिना बिक्री किए ही वापस लौट गए। किसानों का कहना है कि दो दिन पहले भी आलू करीब 300 रुपए कुंतल ही बिका था, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मंडी में पड़े आलू के बड़े-बड़े ढेर बढ़ती गर्मी के कारण काले पड़ने लगे हैं और कई जगह आलू सड़ने की स्थिति में पहुंच गया है।

सरकार कर रही अनदेखी , किसानों को मिला सिर्फ लॉलीपॉप

किसानों का आरोप है कि सरकार ने आलू उत्पादकों को सरकारी खरीद शुरू करने और आलू को दूसरे राज्यों तथा बड़े बाजारों में भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। इसके चलते किसान लगातार घाटे में जा रहे हैं। बढ़ती गर्मी के कारण किसान तेजी से आलू की खुदाई कर दूसरी फसल बोने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन मंडियों में गिरते दामों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया और सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं की गई, तो आलू उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान संगठनों और स्थानीय किसानों ने सरकार से मांग की है कि आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए, सरकारी खरीद केंद्र खोले जाएं और मंडियों में आवक के अनुसार बेहतर प्रबंधन किया जाए ताकि किसानों को उनकी मेहनत की फसल का उचित मूल्य मिल सके।

पिता की सातवीं शादी रोकने थाने पहुंचा नाबालिग बेटा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की सातवीं शादी रोकने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है।

अहरौला थाना क्षेत्र के ग्राम पूरा दुबे गोदाम निवासी शनि मौर्य ने अपने पिता अमरजीत मौर्य के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र देकर उनकी प्रस्तावित शादी रुकवाने की मांग की है। बेटे का आरोप है कि उसके 55 वर्षीय पिता अब तक छह शादियां कर चुके हैं और अब सातवीं शादी की तैयारी में हैं।

शिकायत के अनुसार, अमरजीत मौर्य ने शनि की मां से तीसरी शादी की थी। इससे पहले वह दो शादियां कर चुके थे। बेटे का कहना है कि पिता की छठवीं शादी वर्ष 2024 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी ने जमीन अपने नाम करने की मांग शुरू कर दी। जमीन नाम न होने पर विवाद हुआ और वह घर छोड़कर चली गई। पीड़ित बेटे ने आरोप लगाया है कि अब उसके पिता सातवीं शादी करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए जमीन बेचने का सौदा भी कर लिया गया है और करीब 50 हजार रुपये एडवांस भी ले लिए गए हैं। साथ ही आधे से अधिक जमीन गिरवी रखने की बात भी सामने आई है।

➪ आजमगढ़ के अहरौला क्षेत्र का मामला, 55 वर्षीय पिता पर छह शादियां करने का आरोप

शनि मौर्य ने बताया कि वह 12वीं कक्षा का छात्र है और पढ़ाई के साथ मजबूरी में मजदूरी भी कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि पिता ने उसे जबरन कमाने के लिए बाहर भेज दिया था और वह केवल परीक्षा देने के लिए घर लौटा है। वहीं, घर पर मौजूद बुजुर्ग मां ने पांच शादियां होने की पुष्टि की है, जबकि अमरजीत मौर्य ने खुद स्वीकार किया है कि वह अब तक छह शादियां कर चुका है। इस मामले में अहरौला थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की जा रही है। फिलहाल पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जामताड़ा गैंग के दो साइबर ठग अंडाल स्टेशन से गिरफ्तार

➪ बैंक खाता हैक कर 8.38 लाख की ठगी, 15 मोबाइल फोन और 1.52 लाख नकद बरामद

स्वराज इंडिया ब्यूरो

वाराणसी। साइबर ठगी के एक बड़े मामले में वाराणसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल के अंडाल रेलवे स्टेशन से दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक व्यक्ति के बैंक खाते को हैक कर 8,38,402 रुपये की ठगी की थी।

यह मामला साइबर क्राइम थाना वाराणसी में दर्ज किया गया था। रामनगर क्षेत्र के मछरहट्टा निवासी अनूप गुप्ता ने 5 जनवरी 2026 को शिकायत दी थी कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते को हैक कर 8,38,402 रुपये निकाल लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस व 66ष आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक उदयबीर सिंह को सौंपी गई। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में गठित टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के अंडाल रेलवे स्टेशन से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नागेश्वर मंडल (30) और अक्षय मंडल उर्फ पिन्टू (24) के रूप में हुई है। दोनों फिलहाल पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले के अंडाल क्षेत्र में रह रहे थे, जबकि उनका स्थायी पता झारखंड के जामताड़ा जिले में है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बैंक और आरटीओ चालान भुगतान से जुड़े फर्जी डिजिटल फ्लायर बनाकर लोगों को भेजते थे। इनके साथ एक कूटरचित (मैलिशियस) एपीके फाइल भी होती थी। यह फाइल मोबाइल में इंस्टॉल होते ही ट्रोजन की तरह काम करने लगती थी और आरोपियों को फोन का पूरा एक्सेस तथा आने वाले सभी एसएमएस मिलने लगते थे। इसके बाद वे एसएमएस बॉम्बर के जरिए सैकड़ों मैसेज भेजकर यूजर को भ्रमित करते और इसी दौरान बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर लेते थे। ठगी की रकम टेलीग्राम बॉट के माध्यम से म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कर कार्डलेस पेमेंट के जरिए निकाल ली जाती थी।

बरामदगी और आपराधिक इतिहासः गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 आईफोन, 9 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1,52,100 रुपये नकद बरामद किए हैं। नागेश्वर मंडल के खिलाफ पहले भी झारखंड के जामताड़ा साइबर क्राइम थाने में वर्ष 2021 में साइबर अपराध का मुकदमा दर्ज है।

रामनगरी के मेडिकल कॉलेज में 'दवा बम'!

बिना बिल-वाउचर 139 डिब्बे दवा का खेल, प्राचार्य पर उठे सवाल

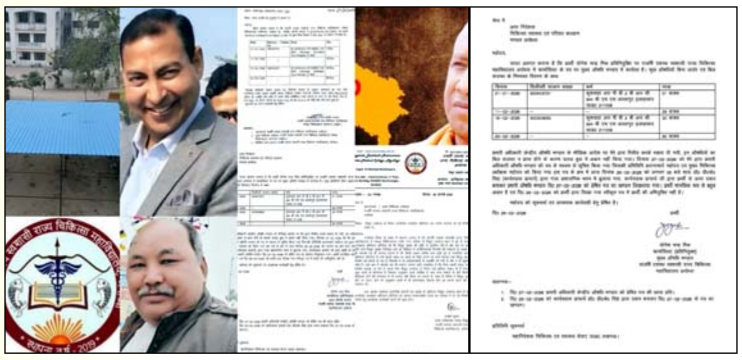

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्याधाम। अयोध्या के राजर्षि दशरथ राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि प्रयागराज से बिना बिल, वाउचर और गुणवत्ता प्रमाणपत्र के 139 डिब्बे दवाएं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दी गईं और उन्हें मरीजों में बांटने की तैयारी भी कर ली गई। मामले के केंद्र में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. दिनेश कुमार मर्तोलिया और उस समय चार्ज में रहे डॉ. दिनेश कुमार सिंह हैं।

सूत्रों के अनुसार जब स्टोर फार्मेसिस्ट योगेश मिश्र ने नियमों के अनुसार दवाओं के जरूरी दस्तावेज मांगे तो उन्हें दबाव में लेकर खंडन पत्र लिखवाने की कोशिश की गई। सूत्र बताते हैं कि फार्मेसिस्ट ने 27 फरवरी 2026 को लिखित रूप से बिल, वाउचर और गुणवत्ता प्रमाणपत्र की मांग की थी। इसके बाद मामला और संवेदनशील हो गया। आरोप है कि प्राचार्य कार्यालय में बुलाकर उन पर दबाव बनाया गया और बाद में उन्हें ही उनकी कुर्सी से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया।

➪ **मरीजों की सेहत से खिलवाड़ या करोड़ों के खेल की तैयारी?**

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मेडिकल कॉलेज से दवा खरीद का कोई क्रय आदेश ही जारी नहीं हुआ, तो प्रयागराज से दवाओं की सप्लाई किसके आदेश पर हुई? और यदि दवा वैध तरीके से खरीदी गई है तो उसके कागजात सामने क्यों नहीं लाए जा रहे?

➪ **फार्मेसिस्ट को हटाने का आदेश कर मामले को दबाने की कोशिश**

मामला सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल कॉलेज परिसर में पावर स्टेशन के पास बिना अनुमति स्थायी कैंटीन निर्माण भी कराया जा रहा था, जिसे बिजली विभाग की शिकायत के बाद पुलिस बुलाकर रुकवाना पड़ा। अब यह पूरा प्रकरण रामनगरी में स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर चल रहे संभावित 'दवा घोटाले' की ओर इशारा कर रहा है।

राम मंदिर परिसर में नई दर्शन व्यवस्था, रोज 5 हजार श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश

➪ **रामनवमी के बाद पास सिस्टम से परकोटा, कुबेर टीला व सप्त मंडपम के भी होंगे दर्शन**

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को परकोटे के छह मंदिरों, शेषावतार मंदिर, सप्त मंडपम और कुबेर टीला के दर्शन कराने के लिए नई व्यवस्था तैयार की है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कराया गया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को पास जारी किए जाएंगे।

नई व्यवस्था के तहत प्रतिदिन करीब 5 हजार श्रद्धालुओं को पूरे परिसर के दर्शन कराए जाएंगे। यह व्यवस्था रामनवमी के बाद लागू की जाएगी। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और परिसर में चल रहे अन्य प्रमुख निर्माण भी अंतिम चरण में हैं। अब श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के सभी महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को ही इस व्यवस्था के तहत प्रवेश दिया जाएगा।

अयोध्या में 'जमीन का जाल'

दूसरे की जमीन दिखाकर 34 लाख की ठगी

➪ **फर्जी कागज, बाउंस चेक और धमकी—पिता, पुत्र व भाई पर मुकदमा दर्ज**

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में जमीन कारोबार के नाम पर ठगी का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरे की जमीन को अपनी बताकर एक व्यक्ति से 34 लाख रुपये ऐंठ लिए गए और जब कब्जा दिलाने की बारी आई तो पूरा खेल खुल गया। नगर कोतवाली पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर कंधारी बाजार निवासी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, उनके बेटे प्रतीक श्रीवास्तव और भाई क्षितिज प्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़ित मो. जुनैद के मुताबिक आरोपियों ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए सभी कागजात वैध होने का दावा किया और 34 लाख रुपये में सौदा तय किया। उन्होंने करीब 20.70 लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए और बाकी रकम नकद देकर स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट कराया, लेकिन जब कब्जा दिलाने की बात आई तो आरोपी टालमटोल करने लगे।

बाद में खुलासा हुआ कि जिस जमीन का सौदा किया गया वह उनकी थी ही नहीं। पीड़ित का आरोप है कि एग्रीमेंट में फर्जी आधार कार्ड भी लगाए गए। शिकायत के बाद आरोपियों ने कुछ रकम लौटाने का नाटक किया और 10 लाख का चेक दिया, जो तीन बार बाउंस हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि रामनगरी में जमीन के नाम पर चल रहे ऐसे फर्जी खेल पर आखिर कब लगेगी लगाम?

श्मशान में भी 'लूट का खेल'! मुफ्त अंतिम संस्कार की सुविधा पर वसूली का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में जहां एक ओर श्रद्धालु मोक्ष की आस्था लेकर आते हैं, वहीं दूसरी ओर श्मशान घाट पर भी कथित वसूली के खेल के आरोप सामने आने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रितेश मिश्रा ने महापौर गिरीश पति त्रिपाठी से मांग की है कि अयोध्या बैकुंठ धाम में इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह की निशुल्क सुविधा के बावजूद लोगों से अवैध वसूली की जा रही है।

रितेश मिश्रा का आरोप है कि कुछ लोग महापौर के नाम का दुरुपयोग कर संस्थाओं के जरिए बाहरी तीर्थयात्रियों से पैसे ऐंठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह सेवा वास्तव में मुफ्त है तो वहां स्पष्ट रूप से "निशुल्क अंतिम संस्कार" का बोर्ड लगाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी शोकाकुल परिवार ठगी का शिकार न हो।सामाजिक कार्यकर्ता ने महापौर से इस मामले में तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि रामनगरी की छवि पर लग रहे इस दाग को रोका जा सके।

अयोध्यासेवक रितेशमिश्रा, Ayodhya City में अमित पाण्डेय और 87 अन्य लोगों के साथ हैं.
17 मिनट ·
मैं अयोध्या के #महापौर #गिरीश #पति #त्रिपाठी जी से निवेदन एवं #मांग करूंगा कि आपके नाम का लोग #दुरुपयोग करते हैं और अपने #संस्था में रखकर बाहरी तीर्थ यात्रियों को #लूटते हैं अयोध्या #बैकुंठ धाम में #इलेक्ट्रॉनिक से जलने वाले सभी #लाश को #निशुल्क व्यवस्था है वहां पर लोगों को #लूट लेते हैं निशुल्क कहीं पर लिखा नहीं है महापौर जी #लिखवा दीजिए बड़ी कृपा रहेगा या #आदेश दे दीजिए मैं स्वयं लिखवा दूं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा महापौर जी को जानकारी दे दे बड़ी #कृपा रहेगा अगर मैं कहता हूं तो #गलत मानते हैं आप लोग #कह दे बड़ी कृपा होगा #रितेश #मिश्रा अयोध्या सामाजिक कार्यकर्ता
Journalist YogeshRashtrwadi Ayodhya और 2...
3

अयोध्या में राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आगाज

मंत्री संदीप सिंह ने किया उद्घाटन, बोले खेलों से होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल में 36वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का मंगलवार को भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और गुब्बारे उड़ाकर किया।

प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विभिन्न मंडलों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। बच्चों के स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।सुल्तानपुर की अनुश्री ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और मशाल दौड़ के साथ प्रतियोगिता शुरू हुई।

राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव और मिल्कीपुर विधायक चंद्रभान पासवान ने कहा कि योगी सरकार में खेलों को बढ़ावा मिला है और ग्रामीण प्रतिभाएं आगे आ रही हैं। इस अवसर पर एडी बेसिक कौस्तुभ कुमार सिंह, बीएसए लालचंद सहित कई अधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे।

तेल पर वैश्विक 'नाकाबंदी' की तैयारी में ईरान

अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहे तो लाल सागर के अहम समुद्री मार्ग पर रोक लगा सकता है तेहरान

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा दबाव बनाने के संकेत दिए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बंद होने के बाद अब तेहरान एक और अहम समुद्री मार्ग बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य को बंद करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहते हैं तो ईरान इस रणनीतिक चोकपॉइंट से जहाजों की आवाजाही रोक सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान के वॉर रूम में इस विकल्प पर गंभीर चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि यदि ईरान के नए नेतृत्व या सैन्य ढांचे पर हमला किया जाता है तो देश इस समुद्री मार्ग को बंद कर सकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध लगभग समाप्त होने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि युद्ध का अंत ईरान तय करेगा। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि यदि हमले जारी रहे तो ईरान अपने क्षेत्र से "एक लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने देगा।"

बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला बेहद संकरा और रणनीतिक समुद्री मार्ग है। यह स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री कड़ी भी बनाता है। यह जलमार्ग अरब प्रायद्वीप में यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच स्थित है और वैश्विक शिपिंग के सबसे अहम चोकपॉइंट्स में गिना जाता है।इससे पहले युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। स्वतंत्र शोध संस्था रिस्टैग एनर्जी के मुताबिक इस मार्ग से रोजाना करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत है। इस मार्ग के बाधित होने से दुनिया भर में ईंधन आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है।पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज उछाल देखा गया है। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर करीब 119.50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि कुछ समय के लिए यह 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब भी चली गई थी। युद्ध के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही फारस की खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस के उत्पादन तथा परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है।

इस संकट का असर प्रमुख तेल निर्यातक देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर भी पड़ रहा है। निर्यात बाधित होने के कारण कुछ देशों को तेल उत्पादन घटाना पड़ा है। ऊर्जा कीमतों में तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने और महंगाई में उछाल की आशंका जताई जा रही है।

क्या ईरान के तेल पर नजर है अमेरिका की?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अब एक नया सवाल तेजी से उभर रहा है क्या अमेरिका की नजर ईरान के विशाल तेल भंडार पर है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने इस आशंका को और हवा दे दी है। हालांकि ट्रंप ने सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि अमेरिका ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि इस विषय पर कुछ लोगों के बीच चर्चा हुई है।मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार जरूर किया गया है, लेकिन फिलहाल इस पर खुलकर बात करना जल्दबाजी होगी। बातचीत के दौरान उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि दुनिया के बड़े तेल भंडार भू-राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा बनते रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका को अपने 'नए दोस्त' से 80 मिलियन बैरल तेल मिला है, जिससे ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई थी।दूसरी ओर, तेहरान ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि अमेरिका का असली उद्देश्य ईरान के तेल संसाधनों पर अवैध नियंत्रण स्थापित करना है। ईरान का कहना है कि यदि वॉशिंगटन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेल संसाधनों पर पकड़ बना लेता है तो दुनिया के लगभग 31 प्रतिशत तेल भंडार पर उसका नियंत्रण हो सकता है। तेहरान का यह भी दावा है कि अमेरिका ने खुलकर स्वीकार किया है कि वह यह युद्ध इजरायल के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है।

ट्रंप बोले- जंग लगभग खत्म, ईरान का पलटवारः 'अंजाम हम तय करेंगे'

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच जंग के भविष्य को लेकर बयानबाज़ी तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान अब लगभग खत्म हो चुका है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने ज्यादातर लक्ष्यों को हासिल कर चुका है और युद्ध अंतिम चरण में है।हालांकि तेहरान ने इस दावे को सीधे चुनौती दी है। ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने साफ कहा है कि भले ही युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजरायल ने की हो, लेकिन इसका अंत कैसे होगा यह ईरान तय करेगा। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि पश्चिम एशिया का भविष्य और इलाके के हालात अब ईरानी सेनाओं के हाथ में हैं और अमेरिकी सेना जंग को अपने तरीके से समाप्त नहीं कर सकती।विश्लेषकों का मानना है कि यह सख्त बयान उस घटना से जुड़ा है, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद देश में गहरा आक्रोश पैदा हुआ था। ईरान ने इसके जवाब में खाड़ी क्षेत्र के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब समेत कई स्थानों पर हमले हुए, जिनसे इलाके में दहशत फैल गई। दुबई में तो हालात ऐसे बन गए कि अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दिया और दुनिया भर के अमीर लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते नजर आए।इस बीच ट्रंप ने एक और सख्त चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित करने की कोशिश की तो अमेरिका की प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा कठोर होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ईरान ने तेल सप्लाई रोकने जैसा कदम उठाया तो अमेरिका का हमला "20 गुना अधिक" शक्तिशाली होगा और ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जिनसे ईरान के लिए दोबारा खड़ा होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। युद्ध की इस तीखी बयानबाज़ी का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण कई देशों में गैस और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत सहित कई देशों में गैस की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में भले ही वॉशिंगटन युद्ध के अंत की बात कर रहा हो, लेकिन तेहरान के तेवर यह संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

हालात को नियंत्रित रखने का भरोसा दिलाया

इस बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती चिंताओं के बीच व्हाइट हाउस ने हालात को नियंत्रित रखने का भरोसा दिलाया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी अस्थायी है और अमेरिकी प्रशासन ने ऊर्जा बाजारों को स्थिर रखने के लिए पहले से ही रणनीति तैयार कर ली थी। उनके अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने से पहले ही संभावित ऊर्जा संकट से निपटने के विकल्पों पर काम शुरू कर दिया था।हालांकि युद्ध के बीच तेल संसाधनों को लेकर उठ रहे सवाल वैश्विक राजनीति के उस पुराने सच की याद दिलाते हैं, जिसमें ऊर्जा और सामरिक हित अक्सर एक-दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया में चल रही जंग केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों पर नियंत्रण की बड़ी भू-राजनीतिक लड़ाई भी दिखाई देने लगी है।

बिहार में राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को, नामांकन वापसी के बाद 6 उम्मीदवार मैदान में

पांच सीटों के लिए छह प्रत्याशी; चार सीटों पर एनडीए की बढ़त, पांचवीं सीट पर मुकाबला रोचक

स्वराज इंडिया ब्यूरो

पटना। बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अब मतदान होना तय हो गया है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। ऐसे में अब 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार नामांकन वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद मैदान में कुल छह उम्मीदवार बचे हैं। चूंकि सीटें पांच हैं और उम्मीदवार छह, इसलिए इस बार लंबे समय बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की स्थिति बनी है। राज्यसभा की इन पांच सीटों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर चार सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि पांचवीं सीट को लेकर मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है।

एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पांचवीं सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार शिवेश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। राजद ने मौजूदा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को एक बार फिर मैदान में उतारा है।

इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को राजद विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता वह स्वयं करेंगे। इस बैठक में विधायकों को मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति और अनुशासन को लेकर निर्देश दिए जाने की संभावना है।

राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि राजद ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से संपर्क किया है। एआईएमआईएम सूत्रों के मुताबिक, समर्थन के बदले पार्टी ने विधान परिषद की एक सीट की मांग की है। हालांकि इस प्रस्ताव पर राजद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इससे पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि राजद की ओर से बातचीत के लिए पहल नहीं होती है तो उनकी पार्टी मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम के पांच विधायकों और बसपा के एक विधायक का समर्थन मिलने पर ही राजद उम्मीदवार की जीत की संभावना मजबूत हो सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है और सभी दल अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुट गए हैं। 16 मार्च को होने वाले मतदान से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पांचवीं

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853,
❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com